

बीएसएनएल : कहीं भीतरघात का शिकार तो नहीं?

मा

रत संचार नियम लिमिटेड (बीएसएनएल) भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) का एक प्रमुख एवं लोकप्रिय उपक्रम है। बीएसएनएल का स्वामित्व दूसरे चार विभाग के पास है और दूसरे चार विभाग संचार मंत्रालय का एक हिस्सा है। भारत सरकार ही बीएसएनएल की 100% शेयर पूँजी का मालिक भी है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौर्मिंडल में संचार मंत्रालय का कामकाज अश्वनी वैष्णव देख रहे हैं जोकि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हालांकि भारतीय संचार क्षेत्र में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल तथा वोडाफोन आइफोन जैसे और भी कई छोटी व क्षेत्रीय निजी कम्पनीज सक्रिय हैं परन्तु इन सभी प्रतिपथ्य होने के बावजूद आज भी बीएसएनएल को देश में सभी अधिक उपभोक्ता रखने का गैरव हासिल है।

आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2024 तक बीएसएनएल के पास देश में लगभग 88.512 मिलियन मोबाइल फोन के ग्राहक थे। इसका मुख्य कारण यह भी था कि देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने जून 24 में ही अपने मोबाइल टैरिफ बढ़ा दिये थे। इसमें रिलायंस जियो ने जून 27 जून को अपने टैरिफ में 12 से 27 प्रतिशत की बढ़ातेरी की थी वहीं भारतीय एयरटेल ने 8 जून को अपना टैरिफ 11 से 21 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। इसी तरह वोडाफोन आईफोन ने भी 29 जून, 24 को अपना टैरिफ 10 से 24 प्रतिशत तक बढ़ा दिया इसी बढ़ातेरी का फौन बढ़ा ही बीएसएनएल में 2.9 मिलियन ग्राहकों की वृद्धि हुई। जबकि निजी दूसरंसंचार कंपनियों को अपने करोड़ों ग्राहकों से हाथ थोना पड़ा। उस समय बीएसएनएल ने घृणी वार ग्राहकों को इतनी वृद्धि दर्ज की थी। जून - जुलाई 24 में बीएसएनएल ने लगभग 2.9 मिलियन उपयोगकारी अपने साथ जाड़।

बीएसएनएल को ऐसा ही एक अवसर उस समय भी हाथ लगा था जबकि 2020-2021 में होने किसान आंदोलन के समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित फैले देश के किसानों द्वारा 2020 में भारतीय संसद द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियमों के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था। उस समय किसान, अंबानी-अडानी द्वारा संचालित उद्यमों व उपक्रमों का भी विरोध कर रहे थे।



किसानों का कहना था कि मोदी सरकार अंबानी-अडानी जैसे निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिये ही तीन कृषि अधिनियम लाई है। इसलिये किसानों द्वारा पांजाब, हरियाणा में रिलायंस जियो का भी खैर पैमाने पर विरोध याहां शहरों तक कि विद्युत किया जा रहा था। रिलायंस जियो के तो कई मोबाइल टारफर्स में भी उस समय तोड़ फोड़ की खबरें आई थीं। बहरहाल जिन उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए निजी कम्पनीज सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन या प्रतीक्षान में खर्च करती हैं वही उपभोक्ता बिना किसी प्रयास के बीएसएनएल को स्वयं ही मिल रहे थे इससे बड़ी लोकप्रियता की बात बीएसएनएल के लिये और बिया होती है। परन्तु चिंता का विषय है कि देश का सभी बड़ा संचार टारफर्क होने के बावजूद नेटवर्क और स्पॉट दोनों ही मामलों में बीएसएनएल अपने में सुधार नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल व हरियाणा यहाँ तक कि चंडीगढ़ में तो

इसकी गति नाममार्द है। सचाल यह है कि देश का सभी बड़ा व सभी साधन सेपन नेटवर्क व सभी अधिक टारफर्स रखने के बावजूद अधिकर क्या बजह है कि गांव में तो दूर शहरों तक इसके पूरे मोबाइल सिमनल नहीं आ पाते? आज के युग में जबकि 5 -10 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक की लादेन मोबाइल गूगल या पे फोन जैसे मामलों से की जा रही हो, ऐसे में अन्य निजी कम्पनीज की ही तरह बीएसएनएल का भी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तीव्र गति के साथ उपलब्ध होना बहुरी है। परन्तु एक तरफ तो दशभक्ति का जज्जा रखने वाले ग्राहकों का बीएसएनएल की ओर आकर्षित होना और दूसरी तरफ बीएसएनएल द्वारा अपने ग्राहकों को इतने तोड़ फोड़ की खबरें आई थीं। बहरहाल जिन उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए निजी कम्पनीज सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन या प्रतीक्षान में खर्च करती हैं वही उपभोक्ता बिना किसी प्रयास के बीएसएनएल को स्वयं ही मिल रहे थे इससे बड़ी लोकप्रियता की बात बीएसएनएल के लिये और बिया होती है। परन्तु चिंता का विषय है कि देश का सभी बड़ा संचार टारफर्क होने के बावजूद नेटवर्क और स्पॉट दोनों ही मामलों में बीएसएनएल अपने में सुधार नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल व हरियाणा यहाँ तक कि चंडीगढ़ में तो दरअसल पिछले एक दशक से ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं तो जिनसे यह पता चलता है कि सरकारें उद्योगपतियों को काँपेरेंट घरानों की हितैशी के रूप में काम कर रही हैं। जिसपरह विद्युत, रेल, बंदरगाह, इंशुरेंस, बैंकिंग, टेल, गैस, कोयला, सेन्य समग्री, विमान व संचार जैसे अनेक क्षेत्रों में सरकारी को सरपरसी में उद्योगपतियों व कॉर्पोरेंट घरानों का दखल बढ़ा है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन उद्योगपतियों के लिये व्यवसायिक आधार तैयार कर कई दशों में इन्हें माझिनग, बिजली व निमांण आदि के टेक विद्युत ये गये हैं उन्हें देखकर यह संदेह होना भी व्यवधानिक है कि कहाँ बीएसएनएल को बदलना चाहिए तो यही तो नहीं किया जा रहा? यदि बीएसएनएल इंडियानदारी से चाहे तो कम से कम समय में अपने उपभोक्ताओं को हो रही रही इन परेशानियों से निजात दिला सकता है। और यदि बीएसएनएल की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निश्चित रूप से निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों द्वारा उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं को बदलना चाहिए तो यही तो नहीं किया जा रहा? यदि बीएसएनएल इंडियानदारी से चाहे तो कम से कम समय में अपने उपभोक्ताओं को हो रही रही इन परेशानियों से निजात दिला सकता है। और यदि बीएसएनएल की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो कम से कम समय में अभी उपभोक्ताओं को हो रही रही इन परेशानियों से निजात दिला सकता है। और यदि बीएसएनएल की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निश्चित रूप से निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निश्चित रूप से निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों में उपभोक्ताओं वे उपभोक्ताओं की ओर से पूरे देश के हर कोने तक अना नेटवर्क के पूरे सिग्नल पूँछा दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभी भी काँपोंट घरानों के हितों के न केवल पैरोकार हैं बल्कि सभी पूँछिए तो उन्हीं के सीधे प्रतिनिधि के रूप में सत्ता की अधिकारी गति में सुधार कर दिया जाये तो निजी कम्पनीज की तरफ से अभ

